Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 243 ▫ रायपुर, शुक्रवार 26 सितम्बर 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ईडी एक्शन में : रायपुर और बिलासपुर में मारा छापा

रायपुर/बिलासपुर, 26 सितंबर (हाईवे चैनल)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने शुक्रवार तड़के बिलासपुर व रायपुर में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बिलासपुर के बड़े व्यापारी मीनाक्षी ट्रेडर्स संचालकों सुल्तानिया परिवार के क्रांति नगर स्थित आवासीय और कारोबारी ठिकानों पर दबिश दी। टीम ने तड़के, दुकान व घर को घेर लिया और बंद कमरों में दस्तावेजों की तलाशी तथा पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं रायपुर के एक बड़े बिल्डर्स के यहां भी छापा पड़ा है,यहां भी दस्तावेजों की पड़ताल चल रही है। जानकारी के अनुसार, सुल्तानिया परिवार के मकान महावीर नगर मंगला चौक के पास में भी स्थित हैं लेकिन वहां ईडी की टीम नहीं पहुंची। छापेमारी फिलहाल केवल क्रांति नगर स्थित घरों और ठिकानों तक सीमित रही। महावीर नगर क्षेत्र में किसी भी तरह की दबिश या तलाशी की खबर नहीं है। छापेमारी वित्तीय लेन-देन और संभावित कोयला कारोबार से जुड़ी गड़बडियों के सुरागों पर केंद्रित है। हालांकि, ईडी ने अभी तक इस कार्रवाई से जुड़ा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इसी तरह, सुल्तानिया परिवार या मीनाक्षी ट्रेडर्स की ओर से भी किसी तरह की टिप्पणी सामने नहीं आई है। फिलहाल टीम क्रांति नगर स्थित मकानों के भीतर कागजातों की जांच और पूछताछ कर रही है। कौन-से दस्तावेज बरामद हुए हैं और जांच किस खास मामले से जुड़ी है। इस पर अभी किसी तरह की पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।

अनुमोदन से पहले शिक्षा विभाग की ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति की सूची सोशल मीडिया पर लीक!

रायपुर, 26 सितंबर (हाईवे चैनल)। स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में प्राचार्यों, व्याख्याताओं और शिक्षकों की प्रस्तावित प्रतिनियुक्ति और ट्रांसफर सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि यह सूची शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के अनुमोदन के बाद भेजी गई थी, लेकिन इसके लीक होने से विभाग की गोपनीयता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं. चूंकि इस सूची को अब तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए इसे अधिकृत नहीं माना जा रहा है।

बुधवार देर शाम अचानक प्रतिनियुक्ति और ट्रांसफर की सूची सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. वायरल इस सूची में शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव का अनुमोदन भी है. माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्री के निवास से अनुमोदन कर सूची को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजा गया था, इसके पहले ही सूची लीक हो गई. मामले में बवाल मचने के साथ ही शिक्षा विभाग में गोपनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

रजिस्टर्ड गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर निर्वाचन आयोग की डी-लिस्टिंग कार्रवाई शुरु

छत्तीसगढ़ में 9 पार्टियों को वार्षिक रिपोर्ट जमा न करने पर नोटिस जारी

रायपुर, 26 सितंबर (हाईवे चैनल)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 334 पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू की है. जिन्होंने (दिसंबर 2018 तक पंजीकृत) पिछले 03 वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) के अपने वार्षिक लेखापरीक्षित खाते निर्धारित समय सीमा, क्रमश: 30.11.2022, 31.12.2023 और 15.12.2024, के भीतर जमा नहीं किए हैं, उन राजनीतिक दलों को रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों की सूची से हटाया जा रहा है. इसके अलावा, ऐसे दल जिन्होंने चुनाव तो लड़े, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यय रिपोर्ट दाखिल नहीं किए, उनके भी नाम हटाने की कार्रवाई की जा रही है. बता दें विधानसभा चुनावों के लिए 75 दिनों की, और लोकसभा चुनावों के लिए 90 दिनों की समय सीमा दी जाती है.

इसी तारतम्य में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चिन्हित कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है. इन राजनीतिक दलों को आयोग के निर्देशानुसार मुख्य निर्वाचन पदाधकारी कार्यालय द्वारा सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाता है . किसी भी रूप को डीलिस्ट करने का अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा. पूर्व में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के 16 राजनीतिक दलों की सूचि प्रेषित की गयी थी जिन्हें आयोग द्वारा दिनांक 09/08/2025 (प्रथम चरण) एवं दिनक 19/09/2025 (द्वितीय चरण) को आदेश पारित किया गया एवं उन्हें आयोग द्वारा पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनितिक दलों की सूची में डिलिस्टेड रूपी के रूप मंण चिन्हांकित किया गया। इसी तारतम्य में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तृतीय चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य 09 पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनितिक दलों को आयोग द्वारा चिन्हांकित किया गया है जिनकी सूची जारी कर दी है, जिन्हें मुख्य निर्वाचन पदाधकारी कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है उनमें भारत भूमि पार्टी 2. भारतीय जनता सेक्युलर पार्टी, 3. भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा 4. छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच 5. छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी, 6. छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी, 7. छत्तीसगढ़िया पार्टी, 8. पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड और 9. राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी शामिल है।

पेट्रोल डालकर कार और बाइक में लगाई आग

कोरबा. 26 सितंबर (हाईवे चैनल)। गांव में दहशत फैलाने की मंशा से अज्ञात लोगों ने कार और दो बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. घटना से गांव में मचे हड़कंप के बीच ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई करने की मांग की है. उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिलकेजा में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात अज्ञात लोगों ने एक इको वाहन और दो मोटरसाइकिलों को आग लगा दी. वाहन मालिक नरेंद्र उरांव ने आगजनी से लाखों रुपए के नुकसान की बात कहते हुए इसे सोची-समझी साजिश का हिस्सा बताया है. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं. इस मामले में कोरबा सीएसपी भूषण एक्का ने बताया कि उरगा थाना पुलिस को सूचना दी गई है. मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है.

ब्रेकिंग न्यूज

माथा पकड़ बैठे शहबाज, मुनीर को भी कराया 30 मिनट इंतजार, ट्रंप ने` पाकिस्तानी पीएम की कर डाली बेज्जइती

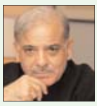

नई दिल्ली, 26 सितम्बर (न्यूज चैनल)। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने गए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की एक बार फिर से फजीहत हुई है। ट्रंप से मिलने के लिए दोनों को इंतजार करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों को करीब आधे घंटे इंतजार करवाया। मुलाकात से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति इस बात को लेकर अनिश्चित दिखे कि दोनों पाकिस्तानी नेता कहाँ होंगे, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें बैठक के लिए देर हो गई है। ट्रंप ने कहा, हो सकता है कि वे अभी इसी कमरे में हों, मुझे नहीं पता क्योंकि हमें देर हो गई है... हो सकता है कि वे खूबसूरत ओवल ऑफिस में कहीं हों। ट्रंप ने शहबाज़ शरीफ़ और असीम मुनीर दोनों को महान व्यक्ति भी बताया।

प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज़ शरीफ़ और फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ने पाकिस्तान-भारत युद्धविराम को संभव बनाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साहसिक, साहसी और निर्णायक नेतृत्व की प्रशंसा की और गाजा में संघर्ष को तत्काल समाप्त करने और मध्य पूर्व में शांति बहाल करने के प्रयासों में प्रमुख मुस्लिम विश्व नेताओं को आमंत्रित करने की उनकी पहल की सराहना की।

लद्दाख की जायज़ मांगें पूरी हों जयराम रमेश ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली, 26 सितम्बर (न्यूज चैनल) ।कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि हालिया हिंसा के बाद लद्दाख के लोगों की पीड़ा और वेदना को देखते हुए भारत सरकार को अपनी अंतरात्मा को जगाना होगा ताकि वह उनकी जायज़ मांगों को पूरी तरह से पूरा करे, न कि सिर्फ़ बातचीत जारी रखे। रमेश ने बताया कि उनकी ज़मीन और रोज़गार के अधिकार ख़तरे में हैं, स्थानीय प्रशासन नौकरशाही के नियंत्रण में है, और छठी अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा और निर्वाचित विधायिका की उनकी मांगों को नज़रअंदाज़ किया गया है।

चूहा- सुनती हो, अब तो शहर में बिना हेलमेट के पेट्रोल मिल रहा है।
चुहिया- हां जी, अव्यावहारिक नीति सफल नहीं होती...!

नदी में बहा निर्माणधीन रपटा पुल ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी

बिलासपुर/सूरजपुर, 26 सितंबर (हाईवे चैनल)।. भारी बारिश से गोबरी नदी पर बना पुल जर्जर होने के बाद नया रपटा पुल का निर्माण कराया जा रहा था. लेकिन पानी के तेज बहाव में यह पुल बह गया, जिससे अब ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है. गांव के दूसरी ओर आने-जाने के लिए लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है. वहीं जिम्मेदार अधिकारियों के कई निरीक्षणों के बावजूद पुल के बह जाने से ग्रामीणों में मायूसी है.

जानकारी के मुताबिक, इस बार बरसात की शुरुआत में ही गोबरी नदी पर बना पुल जर्जर हो गया था. ग्रामीणों ने नए पुल की मांग की थी. बताया जा रहा है कि लगभग 10 लाख रुपए की लागत से रपटा पुल बनाने का फैसला लिया गया था. लेकिन स्वीकृति से पहले ही निर्माणधीन पुल बह गया. 1 से 2 महीने पहले ही ग्रामीणों की मांग पर रपटा पुल का निर्माण शुरू हुआ था. रपटा पुल के बह जाने से ग्रामीणों में फिर मायूसी छा गई है. अब उन्हें आने-जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है.

मोदी आज 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे 10,000 की पहली किस्त, 7,500 करोड़ का बजट

नई दिल्ली, 26 सितम्बर (न्यूज चैनल)। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एनडीए सरकार ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए एक रणनीतिक दांव खेला है। 26 सितंबर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का उद्घाटन करेंगे, जो राज्य की करीब 75 लाख महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को पहली किस्त के रूप में 10,000 सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। कुल मिलाकर सरकार इस योजना के पहले चरण में 7,500 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेगी।

यह योजना बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। योजना के तहत हर परिवार से एक महिला को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। महिलाएं इस सहायता राशि का उपयोग कृषि, डेयरी, सिलाई-कढ़ाई, हस्तशिल्प, ब्यूटी पार्लर या अन्य लघु उद्योगों में निवेश कर सकती हैं। पहले चरण में 10,000 की राशि दिए जाने के बाद, योजना में यह भी प्रावधान है कि यदि महिला अपने व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाती है और प्रगति दिखाती है, तो उसे 2 लाख तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद भी दी जा सकती है। योजना का संचालन जीविका स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा, जो महिलाओं को आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सहयोग भी उपलब्ध कराएंगे। इस योजना को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। विश्लेषकों का मानना है कि यह योजना बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकती है, खासकर महिला वोटर्स के दृष्टिकोण से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि पहले से ही महिला सशक्तिकरण के पक्षधर नेता की रही है- जैसे कि शराबबंदी, लड़कियों की साइकिल योजना और पंचायती राज में आरक्षण जैसे कदमों ने उन्हें महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाया है।

ट्रंप ने लगाया दवाओं पर 100, रसोई कैबिनेट और ट्रकों पर 50 फीसदी टैक्स

नई दिल्ली, 26 सितम्बर (न्यूज चैनल)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपनी व्यापारिक नीतियों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने सीधे दवा उद्योग को निशाना बनाते हुए विदेशी फार्मा कंपनियों पर बड़ा फैसला सुनाया है, जो भारत समेत कई विकासशील और विकसित देशों को प्रभावित कर सकता है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एलान किया कि 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा - अगर वह अमेरिका में निर्मित नहीं हो रही है। यानी, कोई कंपनी यदि अमेरिका में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित नहीं कर रही है, तो उसे इस भारी-भरकम टैक्स का सामना करना पड़ेगा। यह फैसला उन देशों के लिए झटका है जो अमेरिका को बड़ी मात्रा में दवा उत्पाद निर्यात करते हैं। भारत, जो विश्व के सबसे बड़े जेनेरिक दवा उत्पादकों में से एक है, उसके लिए यह निर्णय न सिर्फ आर्थिक, बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई कंपनी अमेरिका में निर्माण कार्य वास्तव में शुरू कर चुकी है, तो उस पर टैरिफ लागू नहीं होगा। आईएस बिल्डिंग का मतलब केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि निर्माण स्थल पर वास्तविक कार्य होना चाहिए।

अमेरिका ने 30 साल बाद 73 वर्षीय महिला हरजीत कौर को बेड़ियों में बांधकर बिना कोई वार्निंग दिए भारत किया डिपोर्ट

नई दिल्ली, 26 सितम्बर (न्यूज चैनल)। डोनाल्ड ट्रंप के कड़े इमिग्रेशन रुख के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अमेरिका में 30 साल से अपने परिवार के साथ रह रहीं 73 वर्षीय हरजीत कौर को बिना कोई वार्निंग दिए भारत वापस भेज दिया गया। पंजाब के मोहाली की रहने वाली हरजीत कौर ने लगभग 30 साल तक अमेरिका में अपने बच्चों और परिवार के साथ जीवन बिताया, लेकिन वैध दस्तावेजों के अभाव में अमेरिकी प्रशासन ने उन्हें भारत भेज दिया। हरजीत कौर की गिरफ्तारी एक रूटीन इमिग्रेशन जांच के दौरान हुई, जिसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में लॉस एंजेलिस से जॉर्जिया तक ले जाया गया और फिर चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा गया। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर रखा गया, जो उनके परिवार और समुदाय के लिए बड़े आघात की बात बनी।

मिग-21 को विदाई : राजनाथ बोले- ये सिर्फ विमान नहीं, भारत के शौर्य का इतिहास है

नई दिल्ली, 26 सितम्बर (न्यूज चैनल)। भारतीय वायु सेना ने शुक्रवार को अपने प्रसिद्ध मिग-21 लड़ाकू विमान को लगभग साठ साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर दिया। चंडीगढ़ में आयोजित एक भव्य सेवामुक्ति समारोह के दौरान इसकी अंतिम उड़ान भरी गई, जिससे भारतीय सैन्य विमानन में एक युग का अंत हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समारोह में भाग लिया और विमान की बेजोड़ विरासत को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लंबे समय से, मिग-21 अनेक वीरतापूर्ण कार्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना या एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि लड़ाकू जेट ने 1971 के युद्ध, कारगिल युद्ध, बालाकोट हवाई हमले और यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर में भी निर्णायक भूमिका निभाई थी। सिंह ने कहा कि ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग-21 ने हमारे सशस्त्र बलों को जबरदस्त ताकत न दी हो। उन्होंने कहा कि लंबे समय से, मिग-21 अनगिनत वीरतापूर्ण कारनामों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना या किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के युद्ध से लेकर कारगिल संघर्ष तक, या बालाकोट हवाई हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग-21 ने हमारी सशस्त्र सेनाओं को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान न की हो। राजनाथ सिंह ने कहा कि मिग 21 महज एक विमान नहीं है, यह भारत-रूस संबंधों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि 1971 के युद्ध को कौन भूल सकता है। पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान, विपरीत परिस्थितियों में, मिग-21 ने ढाका स्थित गवर्नर हाउस पर हमला किया था और उसी दिन उसने उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तैयार कर दी थी।

अंतरराष्ट्रीय अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नामित

स्थानीय निकायों के चुनाव के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए हुआ नामांकित

रायपुर, 26 सितंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के निर्वाचन 2025 के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड के लिए नामांकित हुआ है। आयोग को संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन नेटवर्क की शोध संस्था आईसीपीएस द्वारा अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रबंधन की पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार की अंतरराष्ट्रीय मान्यता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आयोग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को आईसीपीएस ने स्वीकार किया है। आयोग द्वारा नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को एक साथ संपन्न कराने की पहल को आईसीपीएस ने उत्कृष्ट उपलब्धि मानते हुए विजेता अवार्ड, Special Recognition for Outstanding Achievement Award तक के लिए नामांकित किया है।

आईसीपीएस का मुख्यालय लंदन स्थित मिलबैंक टावर में है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (एनडीपी) की सहयोगी है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अध्ययन, अनुसंधान करती है एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए विभिन्न सरकारों को सुझाव देती है। अवार्ड वितरण कार्यक्रम 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2025 के मध्य बोत्सवाना की राजधानी गेबरोने में आयोजित होगा। आईसीपीएस ने आयोग के प्रतिनिधियों को समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। आयोग की ओर से सुखनाथ अहिरवार, सचिव तथा आलोक कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव को अधिकृत किया गया है। शासन से विदेश प्रवास की अनुमति प्राप्त होने पर वे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करेंगे।